Land specific agricultural strategy

*337. SHRIMATI VEENA VERMA: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are contemplating any plan to adopt a land-specific agricultural strategy to raise the foodgrains production level from the current 180 million tonnes to 400 million tonnes over the next three decades; and

(b) if so, the broad features thereof and the steps so far taken to evolve appropriate strategy in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) As per the Planning Commission, the foodgrains production target for 1996-97 and 2006-07 are 210 million tonnes and 286 million tonnes respectively. No projections are available for future years. Present strategy envisages reaching these targets by increasing crop productivity and cropping intensity as well introducing latest technology. This is to be done by adopting a cropping system based approach for an optimal yield as well to ensure sustainable growth not necessarily following any particular land specific agriculture strategy.

(b) In view of reply at (a) above, question does not arise.

Monitoring Cell for un-safe tracks

*338. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Railways have a cell to monitor un-safe tracks;

(b) if so, whether such a cell is in operation in the South-Central Railways;

(c) what are the functions of this cell;

(d) whether it is a fact that the track on the South Central Railways is un-safe; and

(e) if so, what engineering innovations are proposed to be implemented in the South-Central Railways to ensure rail safety?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI RAM VILAS PASWAN): (a) to (c) There is no unsafe track on which trains are running. Track is maintained satisfactorily for the max. permissible speed of the section and the track adequacy is colsely monitored.

(d) No, Sir.

(e) Does not arise.

Delegation for the Atlanta Olympics

*339. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to refer to the answer to Unstarred Question 42 given in the Rajya Sabha on the 12th July, 1996 and state:

(a) which are the States that are sending delegations for the Atlanta Olympics, with the number of the delegates; and

(b) whether Government consider that sending such delegations hepls the development of sports and if not, whether Government will consider banning such delegations as are led by persons who are not sports persons?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI S.R. BOMMAI): (a) and (b) As per information received from the Ministry of Finance (Deptt. of Economic Affairs), the nodal Ministry for clearing the visits of Central/State delagations abroad, Govt. of India have not cleared any such requests received from the State Government.

महानगरों में प्रदूषण

340. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रदूषण स्तर की दृष्टि से भारत और विश्व के प्रमुख नगरों की तुलनात्मक स्थिति क्या है;

(ख) देश के प्रमुख महानगरों में विभिन्न प्रकार के प्रदूषण का वर्तमान स्तर क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) प्रदूषण स्तर को नियंत्रित करने के लिए क्या कारगर कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद): (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से तैयार "विश्व पर्यावरण और स्वास्थ्य" नामक दस्तावेज में उल्लेख किया है कि विश्व के 41 शहरों में से दिल्ली, कलकत्ता और मुम्बई के संबंध में धूलकणों के स्तर क्रमशः चौथा, छठा और तेहरवां हैं जबकि सल्फरडाइआक्साइड के संबंध में 54 शहरों में से दिल्ली का 27वां, मुम्बई का 18वां कलकत्ता का 37वां स्थान है।

(ख) देश के प्रमुख शहरों में सल्फरडाइआक्साइड, नाइट्रोजन के आक्सफाइडों और निलंबित धूलकणों जैसे प्रमुख वायु प्रदूषक तत्वों के प्रदूषण स्तर का दैनिक आधार पर माप किए जाने से इनके स्तरों में वृद्धि की प्रवृत्ति का पता चलता है। सभी शहरों में मलजल-उत्पन्न हो रहा है जो मलजल शोधन की क्षमता से अधिक होता है।

(ग) हमारे शहरों में वायु और जल प्रदूषण की समस्या के कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

— नगरपालिकाओं के पास अपशिष्टों के शोधन के लिए अपशिष्ट सुविधाओं को लगाने के लिए पर्याप्त निधियां नहीं हैं।

— सभी प्रमुख महानगरों में वायु प्रदूषण भार में प्रमुख योगदान मोटरगाड़ियों से उत्सर्जनों के कारण होता है। अधिकांश मोटर गाड़ियों के इंजनों के डिजाइन पुराने हैं जिनसे अधिक प्रदूषण फैलता है। दुपहिए और तिपहिए वाहन जिनकी संख्या काफी है, वे अत्यधिक प्रदूषण फैलाते हैं।

— सभी शहरों में संतोषजनक त्वरित परिवहन प्रणाली की कमी है और सार्वजनिक परिवहन बसों में बड़े तथा परिवहन के अन्य प्रकार पर्याप्त नहीं है जिससे बढ़ती हुई आबादी की अपेक्षाएं पूरी हो सकें। परिणामतः व्यक्तिगत वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है जिससे प्रदूषण भार में अधिक वृद्धि होती है।

— सभी शहरों में पर्याप्त सड़क नेटवर्क तथा अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी कमी है। परिणामतः भीड़-भाड़ और प्रदूषण में वृद्धि हुई है।

(घ) हमारे देश के शहरी पर्यावरण के सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी नेटवर्क के तहत शहरी पर्यावरण की वायु गुणवत्ता की निगरानी की जाती है।

(2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरी नियोजन को सुकर बनाने के ध्येय से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने हक़ बोर्ड का गठन किया है। दिल्ली में गैर अनुकूल क्षेत्रों में स्थिति उद्योगों को अनुकूल क्षेत्रों में स्थानान्तरित होने के लिए कहा गया है।

(3) सरकार लघु उद्योगों के समूह के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक वित्तीय सहायता प्रदान करने संबंधी एक स्कीम को कार्यान्वित कर रही है।

(4) देश के शहरों में सरकार ने ऐसे 22 औद्योगिक पाकेटों / कस्बों / क्षेत्रों का पता लगाया है जो अत्यधिक प्रदूषक क्षेत्र हैं। वहां पर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सामूहिक कार्यवाही शुरू की गई है।

(5) राष्ट्रीय प्रोद्योगिक मिशन के अन्तर्गत शहरी ठोस अपशिष्टों के प्रबंधन पर सिफारिश करने के लिए एक उप-दल का गठन किया गया है। राष्ट्रीय पर्यावरणीय जारूकता अभियान के लिए अपशिष्ट प्रबन्धन को एक विषय के रुप में शामिल किया गया है।

(6) विभिन्न क्षेत्रों में फ्लाई-ऐश के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फ्लाई-ऐश सम्बन्धी एक प्रोद्योगिक मिशन स्थापित किया गया है और राज्य सरकारों को शताब्दी समाप्त होने तक फ्लाई-ऐश की उपयोगिता के लिए संदर्शी कार्य योजनाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। फ्लाई-ऐश से ईंट बनाने के लिए राजकोषीय रियायतें दी जाती हैं।

(7) 01.04.1995 से दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई के चार महानगरों में पैट्रोल तथा उत्प्रेरक परिवर्तक लगे वाहनों को शुरू किया गया है। अब देश के सभी अन्य प्रमुख शहरों को इस कार्यक्रम के तहत लाने की योजना है।

(8) सन् 2000 तक पूरे देश में अति अल्प उत्सर्जन वाले वाहनों और अधिक स्वच्छ ईंधन को शुरू करने हेतु एक कार्यक्रम तैयार किया गया है।

Unscheduled stoppage of Shatabdi Express

1936. SHRI JAYANT KUMAR MALHOUTRA:
SHRI O.P. KOHLI:

Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on Jun 30, 1996, the Kanpur-bound Shatabdi Express made two unscheduled stops at Tundla and Etawah which is unprecedented in the history of the Shatabdi Express;

(b) if so, the circumstances in which the train was detained at the aforesaid stations;

(c) whether any action has been taken against the persons responsible for this; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI SATPAL MAHARAJ): (a) and (b) Train Number 2004 New Delhi-Lucknow Shatabdi Express was stopped out of course at Tundla and Etawah on 30-6-1996 by staff etc. to bid farewell to the driver who was retiring.

(c) and (d) Disciplinary proceedings initiated against the Driver and co-driver.

मध्य प्रदेश के विश्वविद्यालयों में पुनर्मूल्यांकन की सुविधा

1937. **श्री दिलीप सिंह जूदेवः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन विश्वविद्यालयों में घोषित परीक्षाफलों के पुनर्मूल्यांकन की सुविधा उपलब्ध है और किन-किन में उपलब्ध नहीं है;

(ख) वर्ष 1991-92 से 1995-96 तक किन-किन विश्वविद्यालयों में पुर्मूल्यांकन हेतु कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए और इस संबंध में उनमें से कितने आवेदनों को स्वीकृत किया गया और कितने अस्वीकार किये गये;

(ग) उपर्युक्त वर्षों के दौरान प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुनर्मूल्यांकन किये जाने के बाद कितने परिणामों में संशोधन किया गया; और

(घ) मूल्यांकन में असावधानी बरते जाने और पुनर्मूल्यांकन के पश्चात् परिणामों में संशोधन करने की समस्या और इसकी गम्भीरता का आकलन करने के बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और मंत्रालय द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री मुही राम सैकिया): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Support Price for copra

1938. SHRIMATI ANANDIBEN JETHABHAI PATEL: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Agriculture Price Commission has made any recommendations for fixing the support price for copra for 1996 seasons;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether Government have announced the support price for copra for the year 1996; and

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor alongwith the time by which the same is likely to be announced?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI CHATURANAN MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) The Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) in its report on